

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू नहीं होगा ? जाने रिपोर्ट में सामने आई देरी की बड़ी वजहें ।

Publisher

Published on 14 Jun 2025



लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेशनर्स को करना पड़ सकता है और लंबा इंतज़ार, रिपोर्ट में सामने आई नई संभावनाएं ।

नई दिल्ली : देश भर में केन्द्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारी और पेशनभोगी लंबे समय से 8वे वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं । सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि उनकी सैलरी, पेशन और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी । एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, **जनवरी 2026** से आयोग की सिफारिशें लागू होना अब मुश्किल लगता है ।

जनवरी 2026 की डेडलाइन टल सकती है

रिपोर्ट के मुताबिक, 8वे वेतन आयोग की शुरुआत तय समय से टल सकती है । उदाहरण के तौर पर, 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था लेकिन इसकी सिफारिशें **जनवरी 2016** में लागू हुई थीं । ऐसे में अगर **जून 2025** तक भी सरकार नए आयोग के लिए ToR (Terms of Reference) तय नहीं कर पाती है, तो इसका क्रियान्वयन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक टल सकता है ।

सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हो सकते हैं ?

1. अब तक के वेतन आयोगों ने वेतन ढांचे में कई बड़े बदलाव किए हैं:
2. 6वे वेतन आयोग ने पे-बैंड और ग्रेड पे की शुरुआत की थी ।
3. 7वे वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया था ।

8वे वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी में 2.5 से 2.8 गुना तक बढ़ोतरी संभव है।

कर्मचारियों को करना पड़ सकता है और इंतज़ार

हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, **कर्मचारी संगठनों** और **पेशनर्स** की ओर से लगातार मांगें सरकार तक पहुंच रही हैं।

जब तक सरकार आयोग का गठन नहीं करती और **दिशा-निर्देश (ToR)** तय नहीं होते, तब तक किसी भी डेट या सिफारिश को लेकर कोई पुष्टि नहीं की जा सकती।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.